Statement-IV

HUDCO Loan and Central Subsidy released under LCS Scheme (Upto 1997-98) to various states

(Rs. in Lakh)

S.No.	Name of State	Loan Released	Subsidy Released
1.	Andhra Pradesh	1410.37	802.34
2.	Assam	199.23	418.56
3.	Bihar	—	126.73
4.	Goa	400.00	—
5.	Haryana	930.40	1125.56
6.	Jammu & Kashmir	—	181.23
7.	Karnataka	2419.51	741.33
8.	Kerala	166.19	85.84
9.	Madhya Pradesh	610.82	708.49
10.	Maharashtra	1153.17	840.25
11.	Manipur	—	73.45
12.	Meghalaya	52.03	33.34
13.	Orissa	282.93	352.00
14.	Punjab	3924.51	3958.82
15.	Rajasthan	14.22	2077.42
16.	Tamil Nadu	2765.68	866.24
17.	Tripura	—	58.78
18.	Uttar Pradesh	1886.51	2171.87
19.	West Bengal	592.14	2545.08
20.	A & N Islands	12.44	16.50
	GRAND TOTAL:	16829.15	17184.33

शहरी व्यवस्थापन के लिए तकनीकी दल

3645. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग और मंत्रालय द्वारा शहरी व्यवस्थापन, वित्त पोषण और शहरी संदर्श तथा नीति के संबंध में तकनीकी दल गठित किए गये थे;

(ख) क्या उपर्युक्त दलों ने अपनी तकनीकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो कब तक प्रस्तुत कर दी जाएगी; और

(घ) क्या सरकार द्वारा उपर्युक्त दलों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। केवल नगर नियोजन के तकनीकी दल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

शहरी अवस्थापना और शहरी परिदृश्य तथा नीति की वित्त व्यवस्था संबंधी तकनीकी दलों की अंतिम रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

(घ) जी, नहीं। सभी तीनों तकनीकी दलों की अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद ही अनुवर्ती कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है।

अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंध

3646. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंध में सुधार लाने हेतु शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंध हेतु अब तक स्वीकृत की गई कुल निधियों का ब्यौरा क्या है और कितने कस्बों के लिए ये निधियां उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंध हेतु राजस्थान के किसी कस्बे को निधियां उपलब्ध कराई गई हैं और कितने कस्बों ने इस योजना के लिए आवेदन किया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि कम्पोस्ट उत्पादन में नगरीय ठोस अपशिष्ट के उपयोग हेतु प्रायोगिक / निदर्श प्रकल्प स्थापित करने के वास्ते निम्नांकित शहरों / राज्यों को वित्तीय सहायता दी गई है:—

शहर / राज्य	परियोजना लागत (लाख रुपये)	मंजूर की गई राशि (लाख रुपये)
हैदराबाद	436.45	25.00
हिमाचल प्रदेश	88.90	25.00
गाजियाबाद	375.00	25.00

(ग) जी, नहीं।

Encroachments in Basant Gaon

3647. SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO: Will the MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that some persons have encroached Government public passages and established latrin and bathroom etc. in the various colonies of Delhi particularly Basant Gaon (Basant Nagar);

(b) whether Government have received the various representations from the individuals/Association etc. to the Lt. Governor, DDA, MCD, Delhi Police etc. during the last two years and till date regarding unauthorised construction at Government passage;

(c) if so, the details thereof and the reasons therefor; and

(d) the exact time by when Government propose to remove unauthorised construction in Government passages in Basant Gaon, New Delhi?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) to (d) Delhi Police has, reported that one complaint regarding unauthorised construction/encroachment at Basant Gaon near DDA Apartments was received from L.G. House which was sent to DDA for action.

DDA has stated that a report regarding unauthorised construction near House No. 4-B in Khasra No. 33/10 of Village Basant was received from L.G. Office on 10.7.1998 and it demolished the bathroom and boundary wall which was constructed in the area.

MCD has reported that as and when such type of encroachment is noticed,